Millennium Post 07-January-2021

DENSE FOG PREDICTED FOR NEXT TWO DAYS

Rain, hailstorm lash NCR; IMD says Jan saw max rain in 21 yrs

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi has already recorded 56.6 mm rainfall in January, the maximum for the month in 21 years, according to the India Meteorological Department (IMD).

Sporadic rains drenched the national capital for the fourth consecutive day on Wednesday.

The Safdarjung Observatory, which provides representative data for the city, has already recorded 56.6 mm rainfall this January, Kuldeep Srivastava, the head of the IMD's regional forecasting centre, said.

On an average, Delhi records 21.7 mm in January every year. It had gauged 48.1 mm rainfall in January last year, 54.1 mm rainfall in January, 2019 and 59.7 mm in January, 1999.

The city had registered 69.8 mm rainfall in the same month in 1995, according to IMD data.

On Wednesday, the Safdarjung Observatory recorded 6 mm rainfall till 5:30 pm.

The weather stations at Palam, Lodhi Road, Ridge and Ayanagar gauged 5.4 mm, 6.3 mm, 11.1 mm and 3.6 mm rainfall, respectively, during the period.

The rains, under the influence of a strong western disturbance, come on the back of a "severe" cold wave that gripped Delhi in the run-up to new year, the IMD said.

On Friday, the mercury plummeted to 1.1 degrees Celsius, the lowest in 15 years, and "very dense" fog lowered visibility to "zero" metres.

The western disturbance is also causing widespread snowfall in the hills. Once it withdraws, the mercury will fall again to 4 to 5 degrees Celsius, officials said.

Dense fog is likely in Delhi over the next two days, the IMD said.

The downpour on Wednesday also led to waterlogging at various parts of the city, which affected traffic. Taking to Twitter, the Delhi Traffic Police alerted commuters about traffic congestion.

Around 9.03 am, the Delhi Traffic Police tweeted, "Traffic is affected in the carriageway from Azadpur towards Mukarba Chowk due to waterlogging at Panchwati red light. Kindly avoid the stretch."

In another tweet, traffic police said," Traffic is affected in the carriageway from Peeragarhi towards Mundka due to waterlogging. Kindly avoid the stretch." According to police, traffic was affected in the carriageway from Kamal T-Point towards Zakhira due to waterlogging.

Delhi's air turns 'poor'

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi's air quality turned "poor" on Wednesday due to unfavourable meteorological conditions, weather department officials said.

The city's 24-hour average air quality index (AQI) was 226. It was 140 on Tuesday and 151 on Monday.

The city's air quality remained in the "moderate" category on Monday and Tuesday due to rain and strong winds, Kuldeep Srivastava, the head of the India Meteorological Department's regional forecasting centre, said.

However, the winds slowed down on Wednesday and the moisture in the air made the pollutants heavier, he said.

The maximum wind speed was 8 kmph on Wednesday.

Times of India 07-January-2021

'Brahmaputra Aamantran Abhiyaan' event held

Union Minister of State for Jal Shakti and Social Justice and empowerment, Rattan Lal Kataria participated in the Brahmaputra Amantran Abhiyan - a river rafting expedition and a public outreach programme, organized by the Brahmaputra Board at Passighat, Arunachal Pradesh on December 30, 2020. The minister appreciated the

cooperation extended by the Arunachal Pradesh government, led under the leadership of Pema Khandu, towards the IEC campaign started by the Brahmaputra Board. The highlight of the campaign is a tour of rafting, undertaken by the team of NDRF, along the Brahmaputra river passing through the states of Arunachal Pradesh and Assam. The Rafting Expedition and Outreach Programme started on December 23 from Pelling at Arunachal Pradesh and shall terminate at Assameralga in Assam on January 21, 2021. The month-long campaign is titled "Living with the rivers" and is aimed at sensitising people towards the river Brahmaputra.

Deccan Chronicle 07-January-2021

RAIN, CLOUDY SKY MARK RISE IN MIN. TEMP

DC CORRESPONDENT
HYDERABAD, JAN. 6

Surprise light rains, cloudy skies and fog marked the city weather on Wednesday. The clouds and drizzle was attributed to a trough spreading from the Comorin coast of Tamil Nadu, coupled with winds from the Bay of Bengal by officials of the Indian Meteorological Department-Hyderabad (IMD-H).

Speaking to *Deccan Chronicle*, Dr K. Nagaratna, director, IMD-Hyderabad, "There would be very light rains in the city on Thursday. After that we do not predict any rains. The sky, however, would continue to be cloudy."

Till 7.30 pm, the gauges at the Telangana State Development Planning Society (TSDPS) recorded rian at Kandikal Gate (6 mm), OYC Community Hall (3.8 mm), Maruthinagar Mahila Sabha Centre (3.5 mm), Sivarampalli and Khilwat Community Hall, 2.3 mm each. Desite the drizzle and the cloudy skies, the minimum temperature rose to 21.6° Celsius, a rise of about 3°C from Tuesday. The maximum temperature was recorded at 26.2°C.

TILL 7.30 PM, the gauges at the Telangana State Development Planning Society recorded rian at Kandikal Gate (6 mm), OYC Community Hall (3.8 mm), Maruthinagar Mahila Sabha Centre (3.5 mm), Sivarampalli and Khilwat Community Hall, 2.3 mm each.

Dainik Jagran 07-January-2021

पानी लिखेगा विकास की नई कहानी

जलवायु परिवर्तन और दुनियाभर में गहराते जल संकट के बीच विकास की नई कहानी वही देश लिखेगा, जो पानी का धनी होगा। यानी, आज जो देश जितना पानी बचाएगा, वह भविष्य में उतनी ही बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया के छह अरब लोगों के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। भारत इस समस्या की गहराई को समझते हुए जल संरक्षण की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने वर्ष 2024 तक जहां देश के सभी घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना की है, वहीं जल स्रोतों के संरक्षण व विकास पर भी तेजी से काम हो रहा है। नमामि गंगे परियोजना के जरिये गंगा के पुनरुद्धार के साथ-साथ अन्य नदियों की सफाई का काम भी किया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार की मदद और निजी सहभागिता से जल संरक्षण परियोजनाओं को इस साल और गति मिलेगी...

नमामि गंगे व नदी संरक्षण

गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत की थी। इसके तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं। सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी तट विकास, नदी सतह सफाई, घाट एवं शवदाह गृह, सांस्थानिक विकास, पौधा रोपण एवं ग्रामीण जल निकासी प्रणाली के लिए 28,0790 .66 करोड़ रुपये की लागत वाली 310 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इनमें करीब 116 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने पिछले साल नमामि गंगे के लिए 800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। 16 राज्यों की 33 नदियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई परियोजना के लिए गत वर्ष 850 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था। नए साल में गंगा व अन्य नदियों के संरक्षण के काम में तेजी आएगी।

5,745 निर्मित और निर्माणाधीन बड़े डैम हैं देशभर में

2,394 बड़े डैम (सबसे ज्यादा) हैं महाराष्ट्र में

75% डैम 20 साल से हैं पुराने

2.3 करोड़ से अधिक वाटर पंप का इस्तेमाल होता है कृषि कार्य में

70% भूगर्भ जल का सिंचाई कार्य के लिए हो रहा प्रयोग

90% पानी का उपयोग हो जाता है माइक्रो इरीगेशन के जरिये

जल संरक्षण की जरूरत

यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 9 .4 -10 .2 अरब हो जाएगी और तब करीब छह अरब लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाएगी। भारत में भी पानी की मांग में तेजी से इजाफा होगा।

भारत में पानी की मांग की स्थिति (2010) व अनुमान (2025 व 250) अरब घन मीटर में।

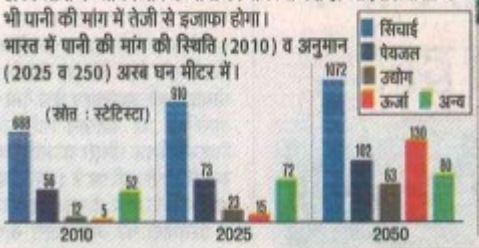

अटल भूजल योजना

संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करने तथा सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इससे इन राज्यों के 78 जिलों को लाभ पहुंचेगा। वर्ष 2024-25 तक पूरी होने वाली इस परियोजना पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसका 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में प्रदान करेगा। भूजल संरक्षण व प्रबंधन की यह योजना नए साल में विस्तार लेगी।

सिंचाई प्रणाली

वर्ष 2010 में देश में फसलों की सिंचाई के लिए 688 अरब घन मीटर पानी की जरूर पड़ी थी। अनुमान है कि वर्ष 2025 में इस कार्य के लिए 910 अरब घन मीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। इसे देखते हुए सरकार सिंचाई की पारंपरिक पद्धति की जगह ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। देश में 210 लाख हेक्टेयर से अधिक में ड्रिप और 500 लाख हेक्टेयर से अधिक में स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई की संभावना है। हालांकि, फिलहाल सिर्फ 2 .13 फीसद में ड्रिप और 3 .30 फीसद में स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई हो रही है।

जल शक्ति अभियान

केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के 256 जिलों के 1592 विकास खंडों में गहराते पेयजल संकट को दूर करने के लिए योजना बनाई गई है। योजना से गत वर्ष तक साढ़े छह करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। 75 लाख से अधिक पारंपरिक व गैर पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार किया गया और करीब एक करोड़ जल संरक्षण व वर्षा जल संचयन ढांचे तैयार किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण गत वर्ष इस दिशा में काम थोड़ा सुस्त पड़ गया था। नए साल में परियोजना के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

हर घर शुद्ध जल

सरकार ने वर्ष 2019 में योजना के तहत पांच वर्षों के लिए 3 .6 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया था, जिसका आधा हिस्सा केंद्र व आधा राज्यों को देना है। वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने इस मद में 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। फिलहाल 6 .01 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के जरिये पानी पहुंच रहा है। नए साल में 3 .2 करोड़ नए घरों तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के साथ-साथ लोगों तक स्वच्छ जल उपलब्ध करना है।

Dainik Jagran 07-January-2021

गति पकड़ेंगी जलाशयों व जल संग्रहण के विकास की योजनाएं

जल बोर्ड की ओर से शुरू अभियान पर अमल का है यह साल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी में पेयजल किल्लत की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने जलाशयों के जीर्णोद्धार व कृत्रिम झील विकसित कर जल संग्रहण और सीवरेज के गंदे पानी को शोधित कर उसे भूजल रिचार्ज के योग्य बनाने की पहल की है। इसके लिए जल बोर्ड की कई योजनाएं हैं। उम्मीद है कि नए साल में जलाशयों व कृत्रिम झीलों के विकास की योजनाएं रफ्तार पकड़ेंगी। कई जलाशयों का इस साल काम पूरा हो सकता है। ये जलाशय भूजल स्तर बढ़ाने में मददगार होंगे। इससे आने वाले समय में जल बोर्ड भूजल से पेयजल आपूर्ति बढ़ा सकेगा। इसके अलावा जल बोर्ड का वर्षा जल संग्रहण की योजनाओं पर विशेष जोर है। पिछले ही माह जल बोर्ड ने वर्षा जल संग्रहण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। यह साल उस अभियान पर अमल का वर्ष का है। इसलिए उम्मीद है कि इस साल मानसून के सीजन में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था दिल्ली में पहले से ज्यादा बेहतर होगी। जल बोर्ड ने इसके लिए सख्ती भी शुरू कर दी है।

दिल्ली में 100 वर्ग मीटर से ऊपर के भूवनों में वर्षा जल संग्रहण होना अनिवार्य है। इस पर अमल नहीं करने वालों के खिलाफ पानी के कुल बिल का 50 फीसद तक जुर्माना किया जा सकता है। जल बोर्ड ने हाल ही में 30 दिन 200 ढांचा का अभियान शुरू किया है। इसके तहत एक माह में वर्षा जल संग्रहण के लिए 200 पिट तैयार करने का लक्ष्य है।

जल बोर्ड ने अपने सभी 42 क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को सख्ती से इसका पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत जल बोर्ड ने आरडब्ल्यूए को भी वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए नोटिस भेजा है। जल बोर्ड 31 मार्च को इस पूरे अभियान की समीक्षा करेगा। जल बोर्ड की यह पहल असरदार साबित हो सकती है। वर्षा जल संग्रहण पिट लगाने पर जल बोर्ड कुल खर्च का 50 फीसद हिस्सा सहायता राशि के रूप में भुगतान करेगा।

312 संपतियां दिल्ली जल बोर्ड की हैं, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है

100 वर्ग मीटर से ऊपर के भवनों में वर्षा जल संग्रहण होना अनिवार्य है दिल्ली में

बाढ़ के पानी का संग्रहण

दिल्ली सरकार पल्ला में 26 एकड़ में छोटे तालाब बनाकर दो साल से यमुना में बाढ़ के पानी को रोककर उसका इस्तेमाल भूजल रिचार्ज करने में कर रही है। यदि सबकुछ ठीक रहा तो इस साल अधिक क्षेत्र में यह प्रयोग किया जा सकता है।

योजनाओं पर होगा अमल : जल बोर्ड ने 376 करोड़ की लागत से 155 जलाशयों के जीर्णोद्धार की पहल की है। इसके तहत 46 जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए टेंडर आवंटित कर चुका है। इसमें से 10 काम पिछले साल ही पूरे होने थे। इसमें इब्राहिमपुर, करावा, दौलतपुर, सिरसपुर, मुंगेशपुर, बिंदापुर, नंगली पूना, टिकरी कलां, नीलवाल व हिरंकी गांव का जलाशय शामिल है। कोरोना के कारण इन जलाशयों के जीर्णोद्धार का काम प्रभावित हुआ है। नए साल में यह काम पूरा होने की उम्मीद है।

कृत्रिम झीलों का विकास : जल बोर्ड करीब 500 एमजीडी सीवेरज शोधित करता है, जबकि सीवेरज के करीब 90 एमजीडी उपचारित पानी का ही गैर घरलू कार्यों में इस्तेमाल हो पाता है। लिहाजा, जल बोर्ड सीवेरज के उपचारित जल से कृत्रिम झील विकसित कर भूजल रिचार्ज करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत रोहिणी, द्वारका, निलोठी व पप्पनकलां सीवेरज शोधन संयंत्र (एसटीपी) के नजदीक कृत्रिम झील विकसित होगी। एसटीपी में उपचारित जल को पहले वेटलैंड में ले जाकर साफ किया जाएगा। इसके बाद उसे जलाशय में छोड़ा जाएगा। इन चार कृत्रिम झील में सीवेरज के करीब 40 एमजीडी उपचारित जल का इस्तेमाल होगा। इससे भूजल स्तर बढ़ सकेगा।

द्वारका में कृत्रिम झील का विकास : द्वारका में कृत्रिम झील तैयार होने पर 50 एमजीडी की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) से शोधन के दौरान निकलने वाले बेकार पानी को दोबारा उपचारित कर व एसटीपी के शोधित पानी को उसमें भरा जाएगा। इससे आसपास के इलाके का भूजल स्तर बढ़ने से आने वाले समय में 15 एमजीडी पानी आपूर्ति बढ़ाई जा सकेगी।

दो अन्य जलाशयों का भी होगा विकास : तिमारपुर आक्सीडेशन पॉंड के पास जलाशय विकसित किया जाएगा। इसके लिए 38 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। आवंटित जमीन के छह एकड़ हिस्से में जलाशय विकसित किया जाएगा और शेष 32 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) को इस परियोजना की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सत्पुला जलाशय के जीर्णोद्धार की भी जल बोर्ड ने पहल की है।

520 स्कूल कालेजों में जल संग्रहण यंत्र बनाए जाने हैं

इन 10 जलाशयों के हो चुके हैं वर्क आर्डर

बिंदापुर	दिसंबर 2019
सिरसपुर व हिरंकी	नवंबर 2019
इब्राहिमपुर, करावा, दौलतपुर व नीलवाल व मुंगेशपुर	अक्टूबर 2019
नंगली पूना व टिकरी कलां	अगस्त 2020

155 जलाशयों के जीर्णोद्धार व सीवरेज के पानी को शोधित कर भूजल रिचार्ज की है योजना

13 एकड़ जमीन में निलोठी एसटीपी के पास जलाशय विकसित कर एसटीपी के उपचारित पानी को संग्रहित किया जाएगा। इसके अलावा पप्पनकलां एसटीपी के पास भी कृत्रिम झील विकसित की जा रही है।

40 एकड़ जमीन में कृत्रिम झील रोहिणी में विकसित होगी। रोहिणी एसटीपी के शोधित पानी को इस झील में एकत्र कर भूजल रिचार्ज की योजना है।

559 भवन सरकारी विभागों के सर्वे के बाद चिह्नित किए गए हैं, जहां वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की जाएगी।

240 भवन दिल्ली सरकार के ऐसे हैं, जिनकी पहचान वर्षा जल संग्रहण के लिए की गई है

Dainik Jagran 07-January-2021

चीन से नए खतरे की दस्तक

विजय क्रांति

ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित नए विशाल बांध का चीन भारत के खिलाफ वाटर-बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है

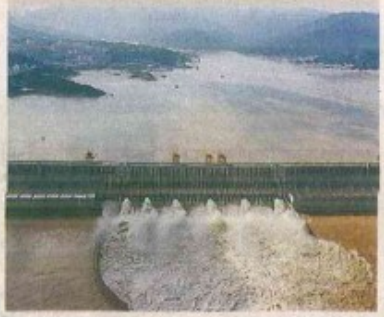

उर्दू के मशहूर शायर मुजफ्फर इस्लाम रज्मी का एक शेर है-'ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।' इसे अगर भारत-चीन रिश्तों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद शायद ही कुछ कहने को बचेगा। 1951 में भारत ने जिस तरह से आंख मूंदकर चीन को तिब्बत पर आराम से कब्जा करने दिया उसके बाद पिछले सत्तर वर्षों में एक भी दिन नहीं बीता जब भारत ने इस गलती की सजा न भुगती हो। इस भयंकर भूल के बाद चीन की सेना आसानी से तिब्बत को लांघकर भारत की हिमालयी सीमा पर आ धमकी। तबसे उसने भारत के खिलाफ जैसी खुराफातों का सिलसिला शुरू किया उसकी फेहरिस्त अंतहीन है।

तिब्बत को आधार बनाकर डोकलाम, अरुणाचल और लद्दाख में चीन की दादागीरी अभी चल ही रही है। इस बीच चीन ने भारत के खिलाफ एक नई तरह के हमले का बिगुल बजा दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषणा की है कि चीन तिब्बत की नदी यारलुंग सांगपो (भारतीय नाम 'ब्रह्मपुत्र') पर भारत की सीमा से ठीक 30 किलोमीटर पहले एक 'सुपर डैम' बनाने जा रहा है, जिसकी क्षमता चीन और दुनिया के सबसे बड़े डैम 'थ्री गॉर्जेस डैम' से भी तीन गुनी होगी। इस पर संभावित खर्च का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 2006 में निर्मित थ्री गॉर्जेस डैम की बिजली क्षमता 22.5 गीगा वाट थी और इस पर 31.7 अरब डॉलर (लगभग 2300 अरब रुपये) खर्च हुए थे। तिब्बत के अंतिम छोर पर प्रस्तावित नए डैम को अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इसकी बिजली उत्पादन क्षमता भाखड़ा नंगल डैम से 111 गुना और भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना टिहरी डैम के मुकाबले 27 गुना अधिक होगी। यानी यह चीनी परियोजना भारत की सबसे बड़ी पांच पनबिजली परियोजनाओं की कुल क्षमता से भी नौ गुना अधिक होगी। चीन इस इलाके में अभी ऐसी दो और परियोजनाओं के लिए भी तैयारी कर रहा है।

चीन की इस घोषणा ने भारत के लिए बहुत गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस परियोजना के लिए चीन जितने बड़े पैमाने पर बांध बनाने जा रहा है वह ब्रह्मपुत्र के बहाव को बहुत प्रभावित करेगा। इसका सीधा असर अरुणाचल प्रदेश और असम की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर होगा। इसका प्रभाव भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों पर भी पड़ेगा, क्योंकि यह नदी भारत के बाद बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस 'सुपर डैम' परियोजना ने भारत के लिए इस सबसे कहीं ज्यादा बड़ा एक जोखिम और भी बढ़ा दिया है। वह यह कि भारत की सीमा के इतने करीब पानी की इतनी विशाल मात्रा को वह भारत के खिलाफ कभी भी एक 'वाटर-बम' की तरह इस्तेमाल करके असम और अरुणाचल में भयंकर तबाही मचा सकता है। ऐसा हमला भारत की नागरिक आबादी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए और विशेष रूप से वहां रक्षा तंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से खतरे की घंटी है।

चीन थ्री गॉर्जेस डैम से बड़ा बांध बनाने की तैयारी में है ● फाइल

चीन के इस 'वाटर-बम' का खतरा कोरी कल्पना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कम से कम तीन अवसर आ चुके हैं जब चीन ने जानबूझकर ऐसे नाजुक मौकों पर भारत की ओर नदियों का पानी छोड़ा जिसने भारत में भारी तबाही मचाई। जून 2000 में अरुणाचल के उस पार तिब्बती क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र पर बने एक डैम का एक हिस्सा अचानक टूट गया जिसने भारतीय क्षेत्र में घुसकर भारी तबाही मचाई। उसके बाद जब भारत के केंद्रीय जल शक्ति आयोग ने इससे जुड़े तथ्यों का अध्ययन किया तो पाया गया कि चीनी बांध का टूटना एक पूर्वनियोजित शरारत थी। उस घटना के कुछ सप्ताह बाद ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भी ठीक ऐसी ही घटना हुई। तिब्बत की ओर से जो पानी अचानक छोड़ा गया उसकी पहली लहर ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसकी ऊंचाई 50 फुट तक थी। उस बाढ़ ने किन्नौर के इलाके में 200 किलोमीटर भीतर तक कहर ढाया। इसी तरह की तीसरी घटना 2005 की पारीचू नदी से संबंधित है। उस समय बाढ़ के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने चीन से इस पानी के बारे में ताजा आंकड़े साझा करने और भारतीय इंजीनियरों की एक टीम को तब तिब्बत में बनी कृत्रिम झील का मुआयना करने की अनुमति मांगी, लेकिन चीन सरकार ने न तो आंकड़े जारी किए और न भारतीय विशेषज्ञों को तिब्बत में प्रवेश की अनुमति दी। रक्षा विशेषज्ञों की चिंता है कि यदि भारत के साथ युद्ध की हालत में या किसी राजनीतिक विवाद में चीन ने ब्रह्मपुत्र पर बनाए गए बांधों के पानी को 'वाटर-बम' की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया तो भारत के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में जानमाल और रक्षा तंत्र के लिए भारी खतरा पैदा हो जाएगा।

इसके अलावा चीन एक और षड्यंत्रकारी योजना पर काम कर रहा है। वह है इस डैम से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल करके पंपों और नहरों की मदद से ब्रह्मपुत्र के पानी को चीन के दूर वाले इलाकों की ओर मोड़ देना। इस तरह की कुछ और योजनाओं पर भी चीन पहले से काम कर रहा है जिनका लक्ष्य वहां से निकलने वाली दूसरी कई नदियों के पानी को अपने उन इलाकों की ओर मोड़ देना है जहां पानी की कमी है। इन योजनाओं का सीधा असर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम समेत दस देशों पर पड़ेगा। इनमें से अधिकांश देश चीन की इस दादागीरी से परेशान हैं। अब सवाल उठता है कि भारत इन देशों के साथ चीन के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने का साहस कब जुटा पाता है?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

Haribhoomi 07-January-2021

महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, भिवानी और दादरी में सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू

नाबार्ड की बैठक में बोले मुख्यमंत्री मनोहरलाल

हर खेत को पानी योजना के तहत पहले चरण में राज्य के चार जिले शामिल

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ चंडीगढ़

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई माइक्रो सिंचाई योजना शुरू की गई है। पहले चरण में इस योजना के तहत चार जिलों-भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया गया है। नाबार्ड ने भी इस योजना पर सब्सिडी देने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का कलस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया करवाया जाएगा।

जल्द ही एक पोर्टल बनाकर इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे जाएंगे। मुख्यमंत्री आज यहां राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 'किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों का समूहन' विषय पर आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2020-2021 के दौरान बोल रहे थे। सेमिनार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल तथा सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टेट फोकस पेपर 2020-2021 का विमोचन भी किया।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने भी कई रचनात्मक सुझाव दिए

किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों का समूहन विषय पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल की बैठक

"देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के कारण बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का जो राहत पैकेज दिया है उसमें से हमें कम से कम 80 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रदेश में लेकर आनी हैं। ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके।

"प्रगतिशील किसानों का मूल्यांकन 8-10 मानकों के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इन किसानों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा एक किसान 10 किसानों को प्रगतिशील बनने को प्रोत्साहित करे। पैरीअर्बन फार्मिंग के तहत एनसीआर में आने वाले जिलों को जरूरत के हिसाब से खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

"राज्य सरकार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी प्रोत्साहित कर रही है। इस दिशा में फसलों की आसानी से बिक्री व उचित मूल्य प्रदान करने के लिए प्रदेश में अब तक 486 एफपीओ बनाए जा चुके हैं। ये संगठन खेती से आय बढ़ाने के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन और प्रसंस्करण सुविधाओं के सृजन का कार्य भी कर सकते हैं।

"राज्य की एक-एक इंच जमीन की पहचान करने के मकसद से स्वामित्व के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। हरियाणा की तर्ज पर ही केंद्र सरकार द्वारा भी अब 6 राज्यों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 3-4 लाख एकड़ लवणीय भूमि है जिसमें से हमें एक साल में एक लाख एकड़ जमीन को ठीक करना है।

Rashtriya Sahara 07-January-2021

पूर्वोत्तर के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बनेगी विकास की धारा

■ विनोद श्रीवास्तव

नई दिल्ली। एसएनबी

केंद्र सरकार ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए पूर्वोत्तर में विकास की धारा बहाने की योजना बना रही है। वह अर्थ ब्रह्मपुत्र योजना के जरिए यहां के लोगों को परिवहन, मालवहन एवं रोजगार सृजन की बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इससे पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक करोड़ लोगों के लिए परोक्ष-अपरोक्ष रूप से रोजगार सृजित होगा। इसके अलावा बांग्लादेश से होकर म्यांमार तक आसान रास्ता बनाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, अंतर्देशीय जल परिवहन के जरिए पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा सकेगा।

केंद्रीय बंदरगाह,जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय अर्थ ब्रह्मपुत्र योजना पर अमल करते हुए अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से जल्द कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगी हुई है। योजना का नाम अर्थ ब्रह्मपुत्र इसलिए रखा गया है, क्योंकि इसका मकसद देश के साथ पड़ोसी देशों के साथ परिवहन एवं मालवहन को बढ़ावा देना है। इन पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार शामिल है। अभी भारत का बांग्लादेश के साथ अधिसूचित प्रोटोकॉल पोर्ट रूट है। इसके माध्यम से बांग्लादेश होकर म्यांमार तक पहुंच हो सकेगी।

पूर्वोत्तर तक पहुंच का विस्तार करने और बांग्लादेश के माध्यम से वैकल्पिक जलमार्ग संपर्क स्थापित करने के लिए नए पहल और उपाय किए जा रहे है। भारत-बांग्लादेश

अर्थ ब्रह्मपुत्र योजना के जरिए परिवहन, मालवहन एवं रोजगार सृजन की योजना

रीजनल कनेक्टिविटी (ईस्टर्न ग्रिड) के जरिए पड़ोसी देश भी जुड़ेंगे जलमार्ग से

प्रोटोकॉल मार्ग पर, बांग्लादेश में 80:20 लागत के आधार पर (भारत द्वारा 80%और बांग्लादेश द्वारा 20%) आशुगंज और जकीगंज (295 किमी) और सिराजगंज और दाइखवा (175 किमी) के बीच तलकर्षण की शुरुआत की गई है। दोनों देशों द्वारा अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन (पीआईडब्ल्यूटीएंडटी) के लिए प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर 20 मई, 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें दोनों देशों की ओर से क्रमशः 5 पड़ाव पत्तन और 2 विस्तारित पड़ाव पत्तन जोड़े गए थे। बांग्लादेश ने समझौते/एसओपी के तहत भारत से वस्तुओं के आवागमन के लिए मोंगला और चट्टोग्राम बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही समझौते के तहत आठ मार्ग उपलब्ध कराए गए है, जिससे बांग्लादेश होते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) तक पहुंच बन सकेगी।

मंत्रालय के अनुसार, हल्दिया से वाराणसी तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1) (गंगा नदी) पर जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत प्रमुख अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) परियोजनाएं निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू-2) (ब्रह्मपुत्र नदी) पर धुबरी और हथसिंगिमारी, नेमाती और कमलाबाड़ी और गुवाहाटी और उत्तरी असम के बीच रो-रो सेवाएं चालू है। एनडब्ल्यू-4 (नदी कृष्णा) के विकास के फेज- के अंतर्गत, विजयवाड़ा और मुक्तियाला के बीच ड्रेजिंग और फ्लोटिंग टर्मिनलों की स्थापना पर काम शुरू किया गया है। एनडब्ल्यू-4 (कृष्णा नदी) पर निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए इब्राहिमपट्टनम और लिंगयापालम के बीच रो-रो सेवाएं भी चालू है। छोटे-छोटे जलमार्गों को जोड़कर पूर्वोत्तर को भी देश के विभिन्न राज्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इससे यहां आर्थिक गतिविधियों का लाभ होगा।

Rashtriya Sahara 07-January-2021

हर खेत को मिलेगा पानी : मनोहर लाल

चंडीगढ़ (एसएनबी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई माइक्रो इरीगेशन स्कीम शुरू की गई है। पहले चरण में इस योजना के तहत भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया है। नाबार्ड ने इस योजना पर सब्सिडी देने पर सहमति जताई है। इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए जल्द एक पोर्टल बनाकर इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे जाएंगे। मनोहर लाल बुधवार को नाबार्ड द्वारा 'किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों का समूहन' विषयक स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2020-2021 में बोल रहे थे।

सेमिनार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल व सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्टेट फोकस पेपर 2020-2021 का यहां विमोचन भी किया। मनोहर लाल ने कहा कि देश व राज्य की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के कारण बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। अर्थव्यवस्था के

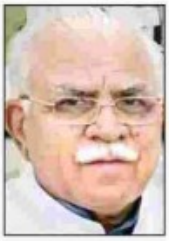

लोगों का जीवन बेहतर बनाने को हमें लाने हैं 80 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट

विभिन्न क्षेत्रों में संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज दिया है, उसमें से हमें कम से कम 80 हजार करोड़ की परियोजनाएं प्रदेश में लेकर आनी हैं, ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके। योजनाएं बनाते समय हमें गरीब से गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ यानी 'अंत्योदय' नहीं हो जाता, तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगतिशील किसानों का मूल्यांकन 8-10 मानकों के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इन किसानों के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा एक किसान आगे कम से कम 10 किसानों को प्रगतिशील बनने के लिए प्रोत्साहित करे। खेती से जुड़ी हर सहायक गतिविधि की लिस्ट बनाकर अलग से योजना बनाएं और 'एक जिला एक उत्पाद' के हिसाब से काम करें। लक्ष्य लंबी अवधि का न होकर एक साल के लिए तय किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बैंक प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए कहा कि लगभग 400-500 गांवों में किसी बैंक की शाखा नहीं है। ऐसे गांव में भी बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत है। इसके लिए 5 गांवों पर एक मोबाइल वैन की व्यवस्था की जा सकती है। मौके पर मुख्यमंत्री ने एफपीओ-शक्तिवर्धक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी हिसार के निदेशक सात्विक और नीलोखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करनाल के चेयरमैन सरदार सिंह को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

इस दौरान नाबार्ड के सीजीएम राजीव महाजन, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक ज्योति कुमार पांडे और एसएलबीसी के कन्वीनर एसए पाणिग्राहि ने विचार रखे। नाबार्ड जीएम बीके बिष्ट ने हरियाणा से जुड़े नाबार्ड प्रोजेक्ट पर प्रजेंटेशन भी दिया। वित्त विभाग के एसीएस टीवीएसएन प्रसाद तथा पीएससीएम वी उमाशंकर ने भी कई रचनात्मक सुझाव दिए।